सरकार के ई-बाजार की चाल पड़ी धीमी; 9 महीने में 50 ऑर्डर भी नहीं आए

पटरी पर लाने को स्टार्टअप व एमएसएमई के प्रोडक्ट्स पर अब टेंडर में छूट की तैयारी

अर्पित शर्मा | जयपुर

राजस्थान सरकार का फ्लिपकार्ट और अमेजन के तर्ज पर शुरू हुआ ई-बाजार प्लेटफॉर्म अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। इस साल किसी भी महीने में 90 से ज्यादा ऑर्डर ही नही आए, जबकि इससे पहले यह संख्या 7 हजार तक पहुंच चुकी है। यह ई-बाजार एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे राजस्थान सरकार ने 2017 में 2017 में ई-कॉमर्स गतिविधियों के लिए एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया था। स्टोर को डायनेमिक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसमें कई स्टोर जोड़े जा सकते हैं। फिलहाल इस पर करीब 28 से ज्यादा विक्रेता हैं और अब तक टोटल 64 हजार से ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। अब तक की इनकम जहां 80.6 लाख है वहीं खर्चा 481. 27 लाख हो चुका है।

पहले 7 हजार से ज्यादा ऑर्डर आते थे

ई-बाजार पर पिछले 9 महीनों में से किसी भी महीने में 50 से ज्यादा ऑर्डर नहीं आए हैं। 2017 में 26,603 ऑर्डर मिले थे। 2018 में 16,494, 2019 में 18,299, फिर 2020 में 2,590 और 2021 में नवंबर तक 529 ऑर्डर मिले हैं।

15 लाख तक के कार्यादेश पर टेंडर में छूट देंगे : नायक

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कमिश्नर संदेश नायक ने बताया कि इसे मजबूत बनाने के लिए विभाग 15 लाख रुपए तक के कार्य आदेश बिना निविदा प्रक्रिया के पंजीकृत स्टार्टअप को ई बाजार पोर्टल माध्यम से देंगे। इसके अलावा ई-बाजार पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के पंजीकृत एमएसएमई के उत्पाद की 10 लाख रुपए की राशि की निविदा के बिना सीधी खरीद का प्रावधान किया जा रहा है।